(b) So far about 40 acres of Government land, and 1048 acres of private land have been acquired for the plant area.

(c) Rs. 1.2 crores have been deposited so far with the Government of Orissa for disbursement.

(d) Upon completion of the project, the total man power requirement is expected to be about 1400. The project is to be completed in two stages. Commercial production is expected to start in Stage-I by 1-3-1986 and in Stage-II by 1-11-1986.

Imoprt of Microwave antannae

10935. SHRI AMAL DATTA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) is it true that the micro-wave antannae are being imported in large numbers; what were the figures of import during the last five years;

(b) is the technology not available in India ; if not, the reasons why it has not been developed; and

(c) have Government failed to develop any indigenous model of ultra high frequency relay system which is an essential part of telecommunication and depends entirely on import ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL) : (a) No, Sir .141 Nos. of microwave antennae of various sizes in different frequency bands were imported in assembled form and in kits directly through M/s. ITI and ECIL during the past 5 years for the use of the P&T Department.

(b) Now the technology is available in India for most of the frequency bands in use.

(c) Ultra High Frequency radio relay system has now been developed indigenously. However, a minimum quantity of such requipment had to be imported to bridge part of the gap between requirement and indigenous production.

हिमाचल प्रदेश में डाकघर और टेलीफोन केन्द्र खोलना

10936. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल कितने डाकघर और टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है और वहां यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1983-84 की वार्षिक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 35 डाक घर खोलने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों में, आत्म निर्भरता के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं जिनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया और इनका खोलना परियात की मांग पर निर्भर करता है तथा इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

1983-84 के दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि धन और सामग्री उपलब्ध रहे।

(ख) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में वायरलेस तार सुविधा उपलब्ध है।

(एक) कालपा (किन्नौर जिला)

(दो) केलोंग (लाहुल स्फीती जिला)

टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने के मामले की जांच की जा रही है। यदि एक्सचेंजों के प्रस्ताव मंजूर हो गए, तो चालू योजना के दौरान खोल दिए जाएंगे।